भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1175

30 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए नियत

**ईवी और आईसीई वाहन के बीच अंतर**

**1175. श्री एस. जगतरक्षकन:**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाले वाहन अपनाने के बीच के अंतर को पाटने के लिए राजसहायता से परे एक व्यापक दृष्टिकोण समय की मांग है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ईवी को अपने आईसीई समकक्षों के लिए एक आशाजनक विकल्प के रूप में उभारा जाना सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

**उत्तर**

**भारी उद्योग राज्य मंत्री**

**(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (ग): जी, हां। भारत में हाईब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण स्कीम, इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन स्कीम 2024, ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम, उन्नत रसायन सेल विनिर्माण के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम जैसी सब्सिडी स्कीमों के अतिरिक्त केंद्र सरकार ने वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं से निवेश आकर्षित करने तथा भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रमुख विनिर्माता के रूप में बढ़ावा देने के प्रयोजन से **भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्धन स्कीम** को दिनांक 15.03.2024 को स्कीम को अधिसूचित किया। अनुमोदित आवेदक कंपनियां 15% के घटे हुए सीमा-शुल्क पर 35,000 डॉलर मूल्य के न्यूनतम सीआईएफ मूल्य सहित उनके द्वारा विनिर्मित ई-चौपहिया वाहनों के 8000 सीबीयू (वार्षिक रूप से) तक का आयात कर सकेंगी, बशर्ते वे न्यूनतम 4,150 करोड़ रूपये के निवेश से ई-चौपहिया विनिर्माण केंद्र स्थापित करें।

इसके अलावा, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित पहलें की हैं:

i. इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जरों/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है।

ii. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी-चालित वाहनों को हरे रंग की लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

iii. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथ-कर माफ करने की सलाह दी है जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती लागत कम करने में मदद मिलेगी।

*****